साप्ताहिक

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 21-27 नवंबर, 2022, वर्ष-8, अंक-33

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में शहडोल से लागू किया गया पेसा एक्ट

सीएम शिवराज ने कहा

मप्र में अब नहीं चलेगा धर्मांतरण का कुचक्र

पावर में ग्राम

अरविंद मिश्र। भोपाल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के मंच से नियमावली का विमोचन कर पेसा एक्ट लागू किया। इस कानून का उद्देश्य आदिवासियों को स्वशासन प्रदा करने के साथ ही ग्राम सभाओं को सभी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाना है। पेसा एक्ट लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ने पेसा कानून बनाए हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे देश में जनजातीय आबादी की संख्या दस करोड़ है। डेढ़ करोड़ से ज्यादा आबादी मप्र में है। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि पेसा एक्ट लागू हो जाने से ग्राम सभा अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है। सामाजिक समरसता के साथ ये कानून हम लागू कर रहे हैं। गांव में तालाबों का प्रबंध अब ग्राम सभा करेगी। चाहे सिंघाड़े लगाएं, चाहे मछली पालें और उससे जो आय होगी वह भी गांव के भाई-बहनों को प्राप्त होगी। इससे होने वाली आमदनी ग्राम सभा को मिलेगी। तालाब में किसी भी प्रकार की गंदगी, कचरा, सीवेज आदि जमा न हो, प्रदूषित न हो, इसके लिए ग्राम सभा किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकेगी। 100 एकड़ तक की सिंचाई क्षमता के तालाब और जलाशय का प्रबंधन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

- » पेसा एक्ट लागू करने वाला मध्यप्रदेश 7वां राज्य बना
- » मध्यप्रदेश में पेसा के नियम 89 ब्लॉक के गांवों में लागू होंगे
- » ग्राम सभा अब वनोपज का संग्रहण करेगी और इसका मूल्य भी तय करेगी
- » गांव में मनरेगा से और अन्य कौन सा काम हो इसे भी ग्राम सभा तय करेगी
- » छल-कपट कर बेटी से शादी कर जमीन हड़पने का काम प्रदेश में नहीं होगा
- » स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी ठीक से चल रहे हैं या नहीं, ग्रामसभा देखेगी
- » अब गांव में शराब की नई दुकानें बिना ग्रामसभा की अनुमति के नहीं खुलेंगी

- » राष्ट्रपति बोलीं-पेसा नियमों का जन-जातीयों के सशक्तिकरण में होगा उपयोग
- » राज्यपाल बोले-जनजातीय वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण करेगा पेसा एक्ट
- » पेसा कानूनः आदिवासियों को जल, जंगल-जमीन पर दिलाएगा अधिकार

जंगल का अधिकार

तेंदुपत्ता तोड़ने और बेचने का अधिकार भी ग्राम सभाओं को दिया गया है। गांव में मनरेगा और अन्य कामों के लिए आने वाले धन से कौन सा काम किया जाएगा, इसे पंचायत सचिव नहीं, बल्कि ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में स्वयं या एक समिति गठित कर वनोपजों जैसे अचार गुठली, करंज बीज, महुआ, लाख, गोंद, हर्रा, बहेरा, आंवला आदि का संग्रहण, मार्केटिंग, मूल्य तय करना और बिक्री कर सकेंगे। एक से अधिक ग्राम सभा भी मिलकर यह काम कर सकती है।

जमीन का अधिकार

यह जमीन, जंगल, जल, खदानें भगवान ने सबके लिए बनाई है। यह हम सबकी है। पेसा कानून के तहत हमने जो नियम बनाए हैं, उसमें जल, जंगल और जमीन का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वनक्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, पटवारी को या बीट गार्ड को गांव में लाकर ग्रामसभा को दिखानी होगी। ताकि जमीनों में हेर-फेर न हो।

अब नहीं चले गा छल-कपट

गैर जनजातीय व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति छल-कपट से, बहला-फुसलाकर, विवाह करके जनजातीय भाई-बहनों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने या खरीदने की कोशिश करें तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप कर सकेगी। यदि ग्राम सभा को यह पता चलता है कि वह उस जमीन का कब्जा फिर से जनजातीय भाई-बहनों को दिलवाएगी। अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना खनिज के सर्वे, पट्टा देने या नीलामी की कार्रवाई नहीं हो सकेगी।

श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण | पेसा के नियम में जो अधिकार दिए गए हैं, वो हमारे गांव से कोई बेटा-बेटी जाएगा तो ले जाने वाले को पहले ग्राम सभा को बताना होगा। ले जाने वाला कौन है, कहां ले जा रहा है, यह भी उसे बताना होगा। ताकि जरूरत के वक्त उनकी मदद हो सकें, बिना बताए ले जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को देखते हुए हमें जनजातीय जीवन-शैली से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। जनजातीय जीवन प्रकृति पर आधारित होता है और वे प्रकृति की रक्षा करते हैं। उनके लिए मानव समाज, वनस्पति जीव-जंतु समान महत्व के है।

द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

जल, जमीन और जंगल का प्रबंधन, छोटे-मोटे विवादों का निराकरण, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, आंगनवाडी केन्द्रों का निरीक्षण, विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग आदि कार्य ग्राम सभा के हाथ में होंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से देश में ग्राम स्वराज की परिकल्पना मूर्तरूप ले रही है।

मंगुभाई पटेल, राज्यपाल

परंपराओं को बचाने का अधिकार

शराब की नई दुकानें बिना ग्रामसभा की अनुमति के नहीं खुलेंगी। शराब या भांग की दुकान हटाने की अनुशंसा का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। यदि 45 दिन में ग्राम सभा कोई निर्णय नहीं करती है, यह मान लिया जाएगा कि नई दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा सहमत नहीं है। फिर दुकान नहीं खोली जाएगी। ग्राम सभा किसी स्थानीय त्यौहार के अवसर पर उस दिन पूरे दिन के लिए या कुछ समय के लिए शराब दुकान बंद करने की अनुशंसा कलेक्टर से कर सकती है। एक वर्ष में कलेक्टर चार ड्राय डे के अंतर्गत दुकान को बंद कर सकेंगे।

इसी विश्वविद्यालय में पढ़े और नौकरी भी यहीं की

डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा बने जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि के कुलपति

भोपाल। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के नए कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा बनाए गए हैं। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। वे 22 नवंबर को प्रभार संभालेंगे। इसी दिन वर्तमान कुलपति डॉ. प्रदीप बिसेन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। डॉ. पीके मिश्रा का कार्यकाल पांच साल का रहेगा। जनेकृवि से ढाई साल पूर्व वे डायरेक्टर रिसर्च के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने जबलपुर कृषि विवि से बीएससी, एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और फिर यहीं से पीएचडी भी की। इसके बाद वे जनेकृवि में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। वे यहां डायरेक्टर रिसर्च, डायरेक्टर फार्म से लेकर डीन फैकल्टी तक रहे। डॉ. मिश्रा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के ससुर हैं। वे भी जनेकृवि के ही छात्र रहे हैं और उन्होंने ग्वालियर कृषि कालेज से बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ली है। उनके लिए आदेश जारी हो चुका। यही जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। कुलपति के रूप में उनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिए होगा।

-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया में की घोषणा

जंगली जानवरों के हमले से मौत पर मिलेगा आठ लाख मुआवजा

- » वन्य प्राणियों से फसल नुकसान की भी मुआवजा राशि बढ़ाई
- » सिंचित भूमि पर नुकसानी पर 30 हजार रुपए कर दी गई

भोपाल। जागत गांव हमार

भोपाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणियों के हमले से मौत होने पर आश्रित परिवार को आठ लाख रुपए मुआवजे की राशि घोषित की है। उल्लेखनीय है कि पहले मुआवजे की राशि चार लाख रुपये थी, जिससे

आश्रित परिवार का गुजर बसर नहीं हो पाती थी। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की राशि को दोगुना करने घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणियों से फसल नुकसान की भी मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। सिंचित भूमि पर नुकसानी होने पर जो पहले 16 हजार रुपए की राशि मिलती थी, अब 30 हजार रुपए कर दी गई है। असिंचित भूमि पर फसल नुकसानी को आठ हजार से बढ़ाकर 16 हजार रुपए किया गया है। किसानों के हितार्थ मुख्यमंत्री की इस घोषणा से किसान खुश हैं, खास तौर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे किसान जिनकी फसल का खतरा हमेशा वन्य प्राणियों से रहता है,उनके लिए ये घोषणा वरदान साबित होगी।

माउंट आबू में नई टेक्निक से खेती का आइडिया आया

आत्मनिर्भर होते अन्नदाता

चार माह ट्रेनिंग ली, सालभर में 20 लाख का मुनाफा

सिवनी। जागत गांव हमार

सिवनी जिले से 38 किमी दूर है देवरी गांव। यहां रहते हैं किसान रवि मानेश्वर। रवि पहले पारंपरिक खेती करते थे। फसलों के दाम अच्छे नहीं मिलने से ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, लेकिन राजस्थान के एक किसान की सलाह ने उनकी जिंदगी बदल दी। रवि ने पारंपरिक खेती छोड़कर मल्चिंग टेक्निक से सब्जी उगाना शुरू किया। प्रयोग के तौर पर 2 साल तक 5 एकड़ में शिमला मिर्च उगाई। रवि को एक साल में 20 लाख का मुनाफा हुआ, तो 15 एकड़ में सिर्फ शिमला मिर्च लगा दी। अब वे उत्तर प्रदेश के बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद, मिर्जापुर के अलावा प्रदेश में जबलपुर और भोपाल तक शिमला मिर्च सप्लाई कर रहे हैं।

किसान दोस्त ने दी थी सलाह

किसान रवि मानेश्वर ने बताया कि वर्षों से पारंपरिक फसल गेहूं, मक्का, मूंगफली और चना की खेती करते आ रहे हैं। अनाज की अधिकांश उपज औसत रहने से अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। इससे निराशा होती थी। 5 साल पहले घूमने के लिए राजस्थान के माउंट आबू गया। वहां के एक किसान राजीव कुमार ने मल्चिंग टेक्निक से सब्जियों की खेती करने की सलाह दी। किसान की सलाह पर मैंने चार साल पहले जबलपुर में जाकर सब्जियों की खेती करने का प्रशिक्षण लिया। जबलपुर से लौटने के बाद पारंपरिक खेती ही करता रहा। कुछ नया करने के लिए पूंजी की जरूरत थी।

इस साल 30 एकड़ में लगाई सब्जियां

2 साल पूंजी जुटाई फिर शुरू की खेती

आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सब्जी की खेती तुरंत शुरू नहीं कर पाया। दो साल बाद पैसे जमा कर इसकी शुरुआत की। पहले ही साल अच्छा मुनाफा हुआ, तो उम्मीद जगी। पहले लागत निकालने की चुनौती होती थी, अब अच्छा-खासा मुनाफा होने लगा। अब हमारे साथ कई किसान खब्जियों की खेती करने लगे। हम टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, भिंडी, लौकी, करेला सहित अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं। मंडी में बेहतर दाम मिलने से पारंपरिक फसलों की तुलना में 4 गुना अधिक फायदा हो रहा है। आसपास के कई किसान पारंपरिक खेती छोड़ सब्जियों की खेती करने लगे हैं। किसानों ने केवल पारंपरिक खेती छोड़ फूल, सब्जी और फल की खेती को अपनाया है।

60-70 मजदूरों को दिया रोजगार

कृषक रवि ने कहा कि सब्जी की खेती को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने से काम की तलाश में पलायन करने वाले मजदूरों को भी अपने क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। यहां 60 से 70 मजदूर रोजाना काम करने आते हैं। इसी तरीके से वे अपना और परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि जिस तरीके से छपारा के आसपास सब्जी की खेती की जा रही है। आसपास के किसान भी पारंपरिक खेती छोड़कर सब्जी उगाने लगे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावना बढ़ गई है।

किसान रवि ने बताया कि पहले मैंने 5 एकड़ में जमीन में सब्जियां लगाकर शुरुआत की। इसमें अच्छा मुनाफा हुआ। इस साल 30 एकड़ खेत में सब्जी लगाई है। किसान रवि ने 15 एकड़ में शिमला मिर्च, 6 एकड़ में टमाटर और बाकी जमीन पर गोभी, मिर्ची, गेंदा फूल, नेपियर ग्रास (दुधारू पशुओं को खिलाने वाली हरी घास), भिंडी, करेला और केला लगाया है। इसमें लगभग 45 लाख खर्च आया। किसान ने बताया कि अभी इसे लगाए सात-आठ महीने ही हुए हैं। अब तक 30 लाख रुपए मिल गए हैं। आने वाले समय में वे ब्रोकली और यलो खरबूज की खेती करने की तैयारी में हैं। वर्तमान में सब्जी की फसल लगाकर पारंपरिक फसल की तुलना में कई गुना लाभ मिल रहा है।

बोवनी से पहले बीजोपचार करना भी जरूरी

गेहूं की खेती: दिसंबर से पहले फसल की बोवनी कर लें किसान

प्रदेश में अब बढ़ने लगी ठिठुरन

भोपाल। जागत गांव हमार

गेहूं की बोवनी को लेकर किसानों के मन में कई तरह की शंका रहती हैं। जैसे कि बोवनी कब करें। बोवनी के लिए कौन से बीज का चुनाव करें या फिर किस विधि से गेहूं की बोवनी करें। किसानों के ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस हफ्ते के पूसा में दिए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने किसानों से ऐसी ही कई जानकारियां साझा की हैं। संस्थान के निदेशक डॉ. अशोक कुमार सिंह गेहूं की खेती के बारे में कहते हैं कि किसान इस समय गेहूं की बोवनी कर रहे हैं। गेहूं की बोवनी समय से कर लें। अगर आप समय से बोवनी की जाने वाली किस्मों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें एचडी-2967, एचडी-3086, एचडी-3226, इसके साथ ही डीबीडब्ल्यू-287 या अन्य किस्में शामिल हैं। तो इनकी बोवनी हर हाल में 20 नवंबर से पहले-पहले कर लें। जैसे-जैसे बोवनी की देरी होगी, वैसे-वैसे पैदावार में कमी आती है, क्योंकि जब बोवनी करते हैं तो जब गेहूं में दाना भरने की अवस्था आती है तो उस समय कई बार गर्म हवाएं चलती हैं, तापक्रम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दाने में वजन कम हो जाता है और इससे पैदावार घट जाती है। साथ ही साथ ही अगर हम फसल को ज्यादा समय देते हैं तो जमीन में जो हम खुराक देते हैं, चाहे वो हमारे फर्टिलाइजर हो या फिर पानी दे रहे हों, उसका भरपूर प्रयोग पौधे द्वारा किया जा रहा हो, और जितनी ठंड मिलती है शुरू की अवस्था में उतना ज्यादा फुटाव होता है। इसलिए समय से बुवाई करना बहुत जरूरी होता है।

गेहूं की बोवनी में बीजोपचार जरूरी

गेहूं की फसल की अगर बीजोपचार के बाद बोवनी करते हैं तो कई तरह के रोगों से बचाया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पादप रोग संभाग के वैज्ञानिक डॉ. एमएस सहारन बीजोपचार के बारे में बताते हैं कि इस समय गेहूं की बोवनी चल रही है, बहुत सारे किसान भाईयों ने गेहूं की बोवनी कर भी ली होगी। गेहूं की फसल में सबसे बड़ी समस्या लूज स्मट (खुला कंडवा) की आती है। इसमें आपने देखा होगा कि फसल बड़ी हो जाती हैं, बालियां आ जाती हैं तो उसमें काला दाना पड़ जाता है। काले दाने में फफूंद के स्पोर होते हैं। इसी तरह की कई और भी बीमारियां हैं जो बीज जनित होती हैं, जैसे कि एक बीमारी करनाल बंट होती है, करनाल बंट से भी दाना काला पड़ जाता है। ये भी फसल कटने के बाद दिखायी देता है। इसी तरह की एक बीमारी हेड स्कैब भी होती है, ये बीमारी उन क्षेत्रों में आती है, जहां नमी ज्यादा होती है।

यह विधि अपनाएं किसान

इस बीमारियों से बचने के लिए डॉ. सहारन सलाह देते हैं कि बीज की बोवनी से पहले बीजोपचार जरूर करें। बीजोपचार के लिए किसानों को कार्बेडाजीम बीजोपचार कर लें। बीजोपचार के लिए दो से ढाई ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर सकते हैं। बीजोपचार करने के लिए सबसे गेहूं के बीज में फंगीसाइड डाल दीजिए, उसके बाद बीज को थोड़ा गीला कर दीजिए, आपको ज्यादा गीला भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि सारी दवाई बीज पर लग जाए। लेकिन बीजोपचार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बीजोपचार की प्रक्रिया छाया में ही करनी चाहिए और इसे छाया में सुखाना चाहिए, इसके बाद अगले दिन बोवनी करनी चाहिए।

-कृषि मंत्री ने अधीक्षण यंत्री को सतत मुआयना के निर्देश

टेल ऐंड के किसानों को प्राथमिकता से पानी उपलब्ध कराएं

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि तवा बांध से सिंचाई के लिए पानी सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। उन्होंने दूरभाष पर अधीक्षण यंत्री जल संसाधन राजाराम मीणा को टेल ऐंड के किसानों को सिंचाई के लिए प्राथमिकता से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पटेल ने अधीक्षण यंत्री को टेल ऐंड पर जाकर मौका मुआयना करने को भी निर्देशित किया है। मंत्री ने अधीक्षण यंत्री जल संसाधन को रबी की सिंचाई के लिए तवा बांध से किसानों को समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नहर के टेल ऐंड से अपर एरिया तक निरंतर मौका मुआयना किया जाकर निगरानी रखी जाए जिससे कि सभी किसानों को समय पर पानी उपलब्ध हो सके। होशंगाबाद, सिवनी मालवा, इटारसी और हरदा के किसानों को उनके लिए निर्धारित की गई मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

गांव में उपलब्ध कराएंगे खाद

मंत्री ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसानों को खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि किसानों को उनके गांव में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। इसका क्रियान्वयन भी हरदा के आदिवासी अंचल के ग्राम काल्या खेड़ी, कांकरदा, पिल्या खाल गाँव से प्रारंभ हो गया है। किसानों ने खाद की गांव पहुंच सेवा पर कृषि मंत्री और सरकार के प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को दी सलाह

उकठा से बचाने बीजोपचार के बाद करें चने की बोवनी

किसान अवरोधी किस्मों का भी करें चुनाव

भोपाल। जागत गांव हमार

इस समय किसान रबी की फसलों की बोवनी कर रहे हैं। चना की फसल प्रमुख रबी फसलों में से एक है, चने की फसल को लेकर किसानों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं जैसे कि इन्हें रोग-कीटों से कैसे बचाया जाए। किसानों के ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस हफ्ते के पूसा में दिए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ ने किसानों से ऐसी ही कई जानकारियां साझा की हैं। संस्थान के पौध संरक्षण और जैव सुरक्षा संभाग के सहायक महानिदेशक डॉ. एससी दुबे बताते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चना एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, इसमें फफूंद के कारण होने वाला म्लानि रोग लगता है, जिसे उकठा रोग भी कहते हैं। वो कहते हैं कि उकठा रोग से किसानों को काफी नुकसान होता है, शुरुआती अवस्था में रोग लगने के कारण 70-80 प्रतिशत की क्षति हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए किसानों को बोवनी के समय से ही ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि यह रोग मृदा जनित है, इसलिए जब भी वो बोवनी करें, बीज को उपचारित जरूर करें। चने के बीजोपचार के बारे में वो कहते हैं कि चने की बीजों का उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम और थीरम दवा की सवा-सवा ग्राम मात्रा लेकर करके या एक-एक ग्राम भी मात्रा लेकर इसे दो-ढ़ाई किलो बीज में मिलाकर उपचारित करें। अगर आपके क्षेत्र में ट्राइकोडर्मा का कोई उत्पाद मिल रहा हो तो उसे लेकर उसकी 6-7 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें।

अवरोधी किस्मों का चुनाव करें

अगर इन रोगों से बचना है तो किसानों को चाहिए कि अवरोधी किस्मों का चुनाव करें, जैसे पुरानी प्रजातियों में पूसा 212 की बोवनी करें। इसके साथ ही पूसा 3042, पूसा 3062 की बोवनी करें। इसके साथ ही कई दूसरी प्रजातियां भी हैं, जिनकी जानकारी किसान अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र पर ले सकते हैं। अगर अवरोधी किस्मों का भी चुनाव करते हैं तो उसका बीजोपचार भी जरूर करें।

तैयार खेतों मे दें पलेवा

किसानों को यह सलाह है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए, गेहूं की बोवनी के लिए तैयार खेतों में पलेवा तथा उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था करें। पलेवे के बाद यदि खेत में ओट आ गई हो तो उसमें गेहूं की बोवनी कर सकते हैं। उन्नत प्रजातियां- सिंचित परिस्थिति- (एचडी 3226), (एचडी 18), (एचडी 3086), (एचडी 2967)। बीज की मात्रा 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरपाईरिफांस (20 ईसी) 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाश उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। समय पर बोई गई सरसों की फसल में बगराडा कीट (पेटेंड बग) की निरंतर निगरानी करते रहें और फसल में विरलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। वर्तमान मौसम प्याज की बुवाई के लिए अनुकूल है। बीज दर 10 किग्रा प्रति हैक्टर। बोवनी से पहले बीजों को केप्टान 2.5 ग्रा. प्रति किग्रा बीज की दर से उपचार अवश्य करें।

आलू की किस्मों की बोवनी करें

वर्तमान मौसम आलू की बोवनी के लिए अनुकूल है। अत: किसान आवश्यकतानुसार आलू की किस्मों की बोवनी कर सकते हैं। उन्नत किस्में- कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति (कम अवधि वाली किस्म), कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी। कतारों से कतारों और पौध से पौध की दूरी 45 ˙ 20 या 60 ˙ 15 सेमी रखें। बोवनी से पहले बीजों को कार्बडिज्म 0 ग्रा. प्रति लीटर घोल में प्रति किग्रा बीज पांच मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुवाई से पहले किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें। इस मौसम में किसान गाजर की बोवनी मेड़ों पर कर सकते है। बोवनी से पहले मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में- पूसा रूधिरा। बीज दर 4.0 किग्रा प्रति एकड़। बोवनी से पहले बीज को केप्टान 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करें तथा खेत में देसी खाद, पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। गाजर की बुवाई मशीन द्वारा करने से बीज 1.0 किग्रा प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है जिससे बीज की बचत तथा उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है।

इस सप्ताह जरूरी ये काम करें किसान

किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाएं। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणे फसलों तक कम पहुचती है, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रकिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वकता बढ़ती है। साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है।

पौधशाला तैयार करने उपयुक्त समय

इस मौसम में किसान इस समय सरसों साग- पूसा साग-1, मूली- जापानी व्हाईट, हिल क्वीन, पूसा मृदुला (फ्रेच मूली), पालक- आल ग्रीन,पूसा भारती, शलगम- पूसा स्वेती या स्थानीय लाल किस्म, बथुआ- पूसा बथुआ-1, मेथी-पूसा कसुरी, गांठ गोभी-व्हाईट वियना,पर्पल वियना तथा धनिया- पंत हरितमा या संकर किस्मों की बुवाई मेड़ों (उथली क्यारियों) पर करें। बोवनी से पहले मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। यह समय ब्रोकली, पछेती फूलगोभी, बंदगोभी तथा टमाटर की पौधशाला तैयार करने के लिए उपयुक्त है। पौधशाला भूमि से उठी हुई क्यारियों पर ही बनायें। जिन किसान भाईयों की पौधशाला तैयार है, वह मौसस को ध्यान में रखते हुए पौध की रोपाई ऊंची मेड़ों पर करें। मिर्च और टमाटर के खेतों में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। यदि प्रकोप अधिक है तो इमिडाक्लोप्रि 0.3 मिली प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें।

सरकार की कल्याण कारी योजनाओं का मिल रहा लाभ

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को मिल रहा है। उन्होंने बैतूल जिले के आमला में नव-निर्मित सामुदायिक चिकित्सा भवन और महाविद्यालय भवन के 6 कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम में यह बात कही। आमला में 9 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक चिकित्सा भवन और महाविद्यालय के नवीन कक्षों का निर्माण किया गया है। सांसद डीडी उइके, विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पंवार और अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

-कृषि मंत्री ने दी आमला को सामुदायिक चिकित्सा भवन की सौगात

कृषि मंत्री ने कहा कि आमला को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से नव-निर्मित 60 बिस्तरीय चिकित्सालय भवन की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत-संकल्पित है। मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना से 5 लाख तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा कार्डधारकों को दी जा रही है। उन्होंने पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि आमला में डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय भवन में 3 करोड़ 53 लाख की लागत से निर्मित किए गए 6 अतिरिक्त कक्षों का लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। सरकार की नई शिक्षा नीति से स्वाभिमानी, पुरुषार्थी, चरित्रवान और देशभक्त पीढ़ी को तैयार करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपेक्षा की कि वे शिक्षित होकर गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। महाविद्यालय भवन में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण के साथ ही गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा मिलेगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समापन अवसर पर कहा

कृषि मेला चंबल-ग्वालियर अंचल के लिए साबित होगा मील का पत्थर

मुरैना। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री व क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मेला चंबल-ग्वालियर अंचल के लिए उन्नत कृषि की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई ठोस उपाय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कृषि मंत्री तोमर को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं से छोटे किसानों को फायदा हो रहा है, वे आगे बढ़ रहे हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज मुरैना में आयोजित वृहद कृषि मेला संपन्न हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि मेले में हजारों किसानों को प्रशिक्षण देकर उनका मार्गदर्शन करने के लिए आईसीएआर सहित देशभर के कृषि संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया। तोमर ने कहा कि हमारा देश और चंबल क्षेत्र भी कृषि प्रधान है। हम कृषि को जितना ताकतवर बनाएंगे, उतना ही ताकतवर देश व चंबल क्षेत्र भी बनेगा। कृषि की अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि देश पर कभी भी कोई संकट आए तो कृषि क्षेत्र उससे उबार सकता है। तोमर ने कहा कि पहले कृषि

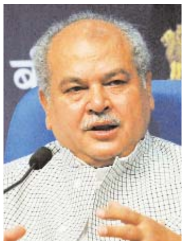

संबंधित योजनाएं उत्पादन केंद्रित थीं लेकिन आज किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित नीतियां अपनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने जबसे कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना से अधिक होनी चाहिए, तबसे केंद्र व राज्य सरकारों और किसानों ने मिलकर इस दिशा में प्रयास किए है। तिलहन की कमी को पूरा करने तथा आयात निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने ऑयल पाम मिशन बनाया, जिस पर 11 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तोमर ने क्षेत्र के किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि किसानों को आज पानी की नहीं, ज्ञानी की जरूरत है, जो कि चंबल के क्षेत्र में देशभर से आए है। इनके ज्ञान से किसान लाभान्वित होने के साथ ही अपनी खेती को उन्नत बनाएंगे। किसान तकनीक का प्रयोग करेंगे तो इसका फायदा नई पीढ़ी को भी मिलेगा और गांवों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

मध्यप्रदेश ने 7 बार कृषि कर्मण अवॉर्ड जीतना

खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री तोमर के नेतृत्व में आयोजित यह कृषि मेला उन्नत खेती के लिए काफी मददगार साबित

होगा। मेले में देशभर में हुए प्रयोगों को किसानों के बीच लाकर किसानों को पारंगत बनाने का प्रयास किया गया है। यहां से किसान जो सीखकर जा रहे हैं, उसके माध्यम से खेती में नए-नए प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री और तोमर के नेतृत्व में खेती में नई-नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, किसानों को अपडेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के लिए बेहतर काम हो रहा है। इसका प्रमाण मध्यप्रदेश द्वारा 7 बार से कृषि कर्मण अवॉर्ड जीतना है।

हमारा देश गांवों का देश

कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि हमारा देश गांवों व किसानों का देश है। मध्यप्रदेश भी कृषि प्रधान है। अटलजी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने गांवों की चिंता की। गांवों में 68 फीसदी बजट खर्च किया, इसी तरह मोदी सरकार ने किसानों की चिंता की व ऐसी योजनाएं बनाई, जिनसे किसानों की आय दोगुना हो व खेती लाभ का धंधा बने। प्रदेश में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण दे रही है। इल्ली से हुए नुकसान को भी आपदा माना गया। मप्र सर्वाधिक फसल बीमा क्लेम देने वाला राज्य है। सरकार ने वन ग्राम को भी बीमा में शामिल किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रयत्न किए गए हैं। यह सब सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन है।

खेती में प्राकृतिक कीटनाशक समय की मांग

डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिण्ड) म.प्र.

कीटनाशकों का मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों की खबरें आए दिन पढ़ने को मिलती हैं। ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा कैंसर जैसे घातक रोगियों की बढ़ती संख्या से आसानी से लगाया जा सकता है। आज खेती-किसानी इन कीटनाशकों पर पूर्णतः आश्रित होकर रह गई है। फसलों में लग रहे कीट, बीमारियां और खरपतवारों के निदान के लिए किसानों के सामने इन कीटनाशकों को प्रयोग करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं रहता है। ऐसे में कीटनाशकों से मानव सहित पशु-पक्षिओं के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए इनका विपल्प तलाशने की जरूरत है।

फसलों से अच्छा और बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्हें पूरी तरह से कीट, रोग, बीमारियों, खरपतवारों और फफूंदीजनित रोगों से बचाने की जरूरत है। यदि किसानों के खेतों में खड़ी फसलें इन सभी समस्याओं से मुक्ति हो जाये तो फसलों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। यदि फसलों में कीट, रोग, खरपतवार की समस्या नहीं हो तो फसल उत्पादन पर आने वाली लागत काफी हद तक कम की जा सकती है। ऐसी स्थिति में एक तरफ किसानों की लागत में कमी आयेगी वहीं दूसरी तरफ उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन यह एक सकारात्मक सोच हो सकती है परंतु हकीकत में ऐसा कभी होगा ऐसा संभव नहीं दिखता है। समय के साथ फसलों में यह समस्याएं और अधिक मुखर हो रहीं हैं। खेती-किसानी के साथ इनसे बचाव का रास्ता भी किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं सरकारों को निकालना ही होगा।

सामांयतौर पर फसलों में प्रयोग किये जाने वाले कृषि रसायनों को कीटनाशक के नाम से ही पुकारा जाता है। जबकि फसलों में तीन तरह के कृषि रसायनों का प्रयोग होता है। जिनमें एक है- कीटनाशी, दूसरा खरपतवारनाशी, तीसरा है फंफूदीनाशी जोकि फसलों में लगने वाले कीट-पंतगों, घास-खरपतवारों एवं रोग-बीमारियों से बचाने में सहायता करते हैं। लेकिन आज फसलों में कीट-रोग, बीमारियों और खरपतवारों के बढ़ते प्रकोप के कारण किसानों की मजबूरी है कि वह इन घातक कृषि रसायनों को यदि प्रयोग ना करे तो उसको फसल पर आने वाली लागत भी निकलना मुश्किल हो जायेगा। ऐसे में खेती को लाभ का धंधा बनाये जाने के प्रयास सिर्फ कागजों तक ही सिमटकर रह जायेंगे। इसलिए किसानों की मजबूरी है कि जब तक इन समस्याओं के निदान का कोई अंय सर्वमांय वैकल्पिक विकल्प नहीं तलाशा जाता है तब तक इन प्राणघातक रयायनों का खेती-किसानी में प्रयोग बंद होने वाला नहीं हैं।

देखने में आ रहा है कि फसलों में लगने वाले कीट, रोग, बीमारियां और खरपतवार साल दर साल और अधिक ताकतवर होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह अनेकों रूप, रंग और प्रजाति बदलकर आ रहे हैं। इसके चलते प्रयोग होने वाली दवाएं बेअसर हो रहीं हैं। परिणाम स्वरूप इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियां और अधिक घातक रसायनों की मात्रा बढ़ाने में लगी हैं जिससे इन पर काबू पाया जा सके। दूसरी तरफ किसान भी जानकार नहीं हैं कि इन रसायनों की कितनी मात्रा, किस अनुपात में, किस समय प्रयोग करनी चाहिए। इस कारण कई बार अनावश्यक रूप से इन रसायनों का असंतुलित प्रयोग भी हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार फल अथवा सब्जियों पर ऐसे रसायनों के प्रयोग के कम से कम एक सप्ताह से 10 दिन बाद ही इनकों तोड़कर बाजार में ब्रिकी अथवा खाने में प्रयोग करना चाहिए।

कुछ वर्षों पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि आम लोग बाजार में जाकर ऐसे फल और सब्जियां खरीदने में ज्यादा रूचि दिखाते हैं जो बेहद चमकदार होती हैं। जिनमें चमक और सफाई ऐसी दिखाई देती है कि मन उन्हें खरीदने

प्रति लालायित होने लगता है। ऐसे फल और सब्जियां खाने से आप गंभीर प्राणघातक रोगों एवं बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। इस प्रकार के फल और सब्जियां आपको हानिकारक कीटनाशकों के अधिकाधिक प्रयोग की वजह से कैंसर, पेट के रोगों सहित अनेक बीमारियां दे सकते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग करके उत्पादित किये जा रहे फल, सब्जी, अनाज, दाले, तेल, दूध आदि से मानव स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ा है। वहीं कीटनाशकों के प्रयोग के चलते पर्यावर्णीय संतुलन बिगड़ा है। खेती-किसानी में सहयोग करने वाले किसानों के मित्र कीट आज पूरी तरह से खेतों से खत्म हो गये हैं। खेती-किसानी के ये ऐसे मित्र कीट थे जोकि शत्रुकीटों को खाकर अथवा नष्ट करके के किसानों की मदद् करते थे।

कीटों के जानकारों के अनुसार कीटों की मुख्यत: दो श्रेणियां हैं-शाकाहारी (जो फसल खाते है) एवं मांसाहारी (जो अन्य कीट खाते हैं) और खेती में दोनों की ही आवश्यकता है। शाकाहारी कीट पौधों की सुगंध एवं रंग आदि से आकर्षित होते हैं और पत्तों की संख्या पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे ही शाकाहारी कीटों की संख्या में जरूरत से अधिक वृद्धि होती है, मांसाहारी कीट स्वत: ही आकर इस वृद्धि पर अंकुश लगा देते हैं। इसी प्राकृतिक संतुलन को कीटनाशक का प्रयोग नष्ट कर देता है। कहा जा सकता है कि कीट नहीं बल्कि कीटनाशक खेती में लाभ से अधिक विनाश करते हैं। इसलिए किसानों को मित्र और शत्रु कीटों की पहचान होना जरूरी है। फसलों में कीट, रोग एवं खरपतवारों की वृद्धि के लिए जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख कारण है। फसलों पर लगने वाले रोग तथा खेतों में पैदा होने वाले खरपतवार के लिए भी किसान कीटनाशकों पर निर्भर रहता है।

बाजार में बिकने वाले कीटनाशक कितने खतरनाक और जहरीले हैं इसकी जानकारी किसानों को होना जरूरी है। फसलों में प्रयोग किये जाने वाले कीटनाशकों के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में भी घटनाएं ब ़ी हैं। आज फसलों पर प्रयोग होने वाले कीटनाशकों के डिब्बों पर लाल, पीला, नीला एवं हरा तिकोना निशान होता है। यह तिकाने रंग के निशान कीटनाशक रसायन की तीव्रता के बारे में जानकारी देते हैं। किसानों चाहिए कि विशेषज्ञों की परामर्श के बाद ही जितनी जरूरत हो उतनी ही मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करें। कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि यह मानव सहित अन्य जीव-जंतुओं के लिए घातक हो सकते हैं।

प्राकृतिक खेती में रोग एवं कीटों पर नियंत्रण के लिए कई घटकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। जिसमें नीमास्त्र, ब्रम्हास्त्र, अग्निआस्त्र, नीम तेल जैसे कई पेड़-पौधों की पत्तियों, फलों, फूलों गौमूत्र आदि से तैयार करके प्रयोग किये जा सकते हैं। हांलाकि अभी अनुभवों के आधार पर देखा गया है कि प्राकृतिक तौर से बनाई जा रहीं कीटनाशक दवाएं खरपतवारों पर बिल्कुल प्रभावी नहीं हैं। फसलों से खरपतवारों को निराई-गुड़ाई करके अथवा प्राकृतिक खेती के घटक आच्छादन का प्रयोग करके काबू में रखते हुये उत्पादन लिया जा सकता है। कीटनाशकों के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुये आज प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करने की जरूरत है। प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग प्राकृतिक खेती में करते हुये सह-अस्तित्व के सिद्धांत को अपनाना होगा तभी प्राणघातक होते जहरीले कीटनाशकों पर काबू पाकर मानव जाति के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख पाना संभव हो सकेगा।

अभी दुनिया के लगभग एक अरब लोग खुले में शौच को मजबूर

विश्व शौचालय दिवस

19 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व शौचालय दिवस (वर्ल्ड टॉयलेट डे) के रूप में नामित किया गया था। हर साल इसे संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की सरकारों के बीच एक साझेदारी द्वारा समन्वित किया जाता है। आज हम एक ऐसे आविष्कार के बारे में बात करते हैं जिसे बंद दरवाजों के पीछे छिपा कर रखा जाता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। विश्व शौचालय दिवस वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत विकास लक्ष्य 6 :2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता हासिल करने के लिए कार्रवाई करने के बारे में है।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आज भी 3.6 अरब लोग खराब गुणवत्ता वाले शौचालयों के साथ रह रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य को खराब करते हैं तथा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) के मुताबिक हर दिन पांच साल से कम उम्र के 1,300 से अधिक बच्चे गंदा पानी पीने तथा गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। वहीं दुनिया भर में लगभग 89.2 करोड़ लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं, जिससे लोगों को पानी और स्वच्छता से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

विश्व शौचालय दिवस का इतिहास: सिंगापुर के एक परोपकारी व्यक्ति जैक सिम ने 19 नवंबर, 2001 को विश्व शौचालय संगठन की स्थापना की, जिसके बाद इस दिन को विश्व शौचालय दिवस घोषित किया गया। डब्ल्यूटीओ ने सार्वजनिक संदेश में आसानी के लिए विश्व स्वच्छता दिवस के विपरीत विश्व शौचालय दिवस को चुना, हालांकि शौचालय स्वच्छता उपकरण का केवल पहला चरण है।

विश्व शौचालय दिवस व्यापक स्वच्छता प्रणालियों जैसे अपशिष्ट जल उपचार, जल प्रबंधन और हाथ धोने के बारे में जन जागरूकता फैलाने और बढ़ाने के लिए बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 6 पर्याप्त स्वच्छता की मांग करता है, जिसमें यह सुनिश्चित करने वाली प्रणाली शामिल है कि कचरे को सुरक्षित रूप से संसाधित किया जाता है।

स्वच्छता संकट पर ध्यान आकर्षित करने के उनके प्रयासों को 2010 में और मजबूत किया गया था जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा पानी और स्वच्छता के अधिकार को आधिकारिक तौर पर मानव अधिकार घोषित किया गया था।

2013 में, सिंगापुर सरकार और विश्व शौचालय संगठन के बीच एक संयुक्त प्रयास ने सिंगापुर के पहले संयुक्त राष्ट्र संकल्प को सभी के लिए स्वच्छता कहा। इस संकल्प ने विश्व स्वच्छता संकट को समाप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। नतीजतन, विश्व शौचालय दिवस को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया गया और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67 वें सत्र में 122 देशों द्वारा इस संकल्प को अपनाया गया। विश्व शौचालय दिवस 2015 के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान

की मून ने सभी के लिए संतोषजनक स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करने के प्रयासों को नवीनीकृत करने के लिए कार्रवाई की वकालत की, सभी को स्वच्छता पर कार्रवाई के लिए कॉल की याद दिला दी, जिसे 2013 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य 2025 तक खुले में शौच को समाप्त करना है।

क्या है विश्व शौचालय दिवस 2022 की थीम ?: विश्व शौचालय दिवस 2022 की थीम स्वच्छता और भूजल है तथा अभियान का शीर्षक मेकिंग द इनविजिबल विजिबल अथवा अदृश्य को दृश्य बनाना है, जो विश्व जल दिवस 2022 के समान है।

बीमारियों से बचाएगी जहरमुक्त खेती

जलवायु परिवर्तन के कारण इस बार फसलों का उत्पादन कम हुआ है, उसका परिणाम है कि महंगाई भी बढ़ रही है और आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें भी महंगी हो चुकी हैं। सभी क्षेत्रों में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। अब जब आपको आसानी से उपलब्ध सस्ते जहरयुक्त अनाज, दाल, तेल, और मसालों की आदत हो गई है, तो अब यही सामान आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। उसी प्रकार से किसानों को भी अपने खेत में रसायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल की आदत हो गई है। इनके इस्तेमाल के बावजूद उत्पादन गिर रहा है, फिर भी रसायनिक खादों और कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल करने वाले किसानों की आंखें नहीं खुल रहीं। उन्हें इतना समझ नहीं आ रहा कि उत्पादन का सीधा सम्बन्ध वातावरण से है, न कि रसायनिक खादों से। उत्पादन प्रकृति की एक व्यवस्था है जो कि आसपास के वातावरण पर निर्भर है।

यदि आपके यहां का वातावरण प्रदूषण रहित रहेगा और विविधता रहेगी तो उत्पादन भी अच्छा रहेगा। चाहे जनता हो, नीति-निर्धारक हों या चाहे किसान, सभी को जो चीजें आसानी से मिल रही हैं उनको पहुंचाने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को समझें और प्रकृति को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण आ रहीं अनिमंत्रित आपदाओं से निजात पाने के लिए और किसानों को जहरीले कीटनाशकों से निजात दिलाने के लिए जमीनी परिवर्तन करें। उन किसानों के बारे में सोचें जो आपको जहरमुक्त अनाज उपलब्ध कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही उन किसानों के बारे में भी सोचें जो सस्ता, परंतु जहरयुक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए कितना रसायन अपने खेत में डाल रहे हैं, अंधाधुंध कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं और ढेरों बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इन किसानों के बारे में सोचें, ताकि ये किसान भी इस रसायनिक खाद और कीटनाशक वाली व्यवस्था से बाहर निकल सकें। इन किसानों से जनता जहरमुक्त अनाज, फल व सब्जियों की मांग कर सकती है, क्योंकि बिना मांग के भला कोई क्यों उत्पादन करेगा।

जब जहरयुक्त अनाज ही आसानी से बिक रहा है तो भला क्यों किसान जहरमुक्त अनाज उत्पादन करने की परेशानी झेलेगा? अगर जनता खुद चाहेगी कि उसको जहरयुक्त अनाज नहीं खाना तो किसान भी जहरमुक्त अनाज के उत्पादन की ओर नहीं जाएगा। नहीं तो यह जहरयुक्त खेती यूं ही चलती रहेगी, बल्कि और तेजी से बढ़ेगी और उसी गति से बढ़ेंगी बीमारियां भी। यह मानकर चलिए कि आपको बीमारियां तो होंगी ही और यह भी ध्यान रखिये कि आप सोना, चांदी, पैसा या सुविधा को खा नहीं सकते, खाने का काम तो खाना ही करेगा। इसलिए अभी भी वक्त है परेशानियों को खत्म करने का। कोरी बातें करने का समय अब निकल चुका है, अब समय है आसानी से हो रही परेशानियों से बचने के लिए जमीनी काम करने का।

इंजीनियर लोगों को नि:शुल्क में बांट रहा सब्जिया, 2.5 बीघा से की शुरुआत, अब 20 बीघा में खेती

जैविक खेती से किस्मत बदल रहा शिवपुरी का धीरज

चुनौतियों से निपट खेती को बनाया लाभा का धंधा

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

शिवपुरी जिले के रामनगर गधाई गांव के किसान धीरज हरनाम सिंह रावत ने इंदौर से इंजीनियरिंग की। खेती से ऐसा मन लगा कि इंजीनियरिंग छोड़ दी। 2.5 बीघा में पहली बार जैविक खेती शुरू की। 65 हजार रुपए की सब्जियां गांव में बांट दी, ताकि लोग इसका स्वाद चखें। इनके फायदे जान सकें। पिता पहले से खेती करते आ रहे हैं, इसलिए नौकरी के बजाय नई तकनीक से खेती करने की सोची। धीरज चाहते हैं कि गांव के दूसरे लोग भी रासायनिक खेती छोड़ जैविक खेती करें। रावत का कहना है कि मैंने पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए बाहर जाने के बजाय खेती को अपनाया। यहां चुनौती थी कि पारंपरिक खेती में लागत और मुनाफे का अंतर काफी कम होता जा रहा है। कई बार नुकसान ही होता है। पिता लंबे समय से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, इसलिए मुझे इसका अनुभव है। यही वजह रही कि मैंने जैविक खेती करने की ठानी। इसमें मुश्किलें थीं, लेकिन हौसला भी था। फिर क्या था। मैंने पिता को मंशा बताई। उनके मार्गदर्शन में मैंने पहले आधे बीघा खेत को तैयार किया। इसमें सब्जियां लगाईं। खाद भी खुद ही तैयार किया। मैंने न सिर्फ खेत से जैविक खेती की शुरुआत की, बल्कि इसकी उपज गांव के लोगों को बांटता रहा। इसकी एकमात्र वजह थी कि लोग जैविक खेती के महत्व को समझें। पहली बार मैंने 2.5 बीघा में सब्जियां उगाईं। इससे जो उपज मिली, उसे लोगों में बांट दिया। 2.5 बीघा खेत में उपजी 200 किलो ककड़ी, 400 किलो लौकी, 400 किलो टमाटर, 200 किलो भिंडी, 50 किलो खरबूज और 30 किलो तुरई गांव के लोगों में बांट चुका हूं। इसे खुले बाजार में बेचा जाए, तो करीब 60-65 हजार रुपए तक मिल सकते थे, जबकि ये सिर्फ आधे साल की कमाई है। अब अगले महीने से जो उपज मिलेगी, उसे बाजार तक लेकर जाऊंगा। साथ ही, लोगों में जागरूक करने के लिए सब्जियों का नि:शुल्क वितरण करता रहूंगा।

अब 20 बीघा में खेती

लौकी, तुरई, धनिया, भिंडी, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं। ककड़ी और खरबूजा की भी खेती कर चुके हैं। इस बार धीरज 5 बीघा में सब्जियों की खेती और 15 बीघा खेत में गेहूं, सरसों, उड़द, मूंग, चना और मूंगफली की खेती कर रहे हैं।

सरसों और गेहूं की खेती

सरसों और गेहूं की खेती जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से कर रहे हैं। धीरज का कहना है कि सब्जियों की खेती में प्रयोग सफल रहा है। इसके मोटे अनाज पर भी आजमाना चाहते हैं। पहली बार इन ये दोनों फसलें दोनों तरीके से लगा रहे हैं। दोनों की पैदावार की स्थिति देखने के बाद अगले साल पूरी तरह से जैविक खाद से मोटे अनाज की खेती शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा दवा सब्जियों में डाली जाती हैं। इससे सब्जी की गुणवत्ता और स्वाद पर भी असर आने लगता हैं। जैविक खेती से मोटे अनाज का प्रयोग सफल रहा, तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।

पशुपालन से खुला जैविक रास्ता

धीरज रावत कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जैविक खेती करना और आसान हो जाता है, जो पशुपालन भी करते हैं। धीरज विकास प्रस्फुटन समिति रामनगर गधाई के अध्यक्ष भी है। उनके यहां भी पशुपालन होता है, इसलिए खाद बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गोबर उपलब्ध हो जाता है। गोबर की खाद मवेशियों के ठोस व द्रव मल-मूत्र का एक सड़ा हुआ मिश्रण होता है। इसमें सामान्यत: भूसा, बुरादा, छीलन अथवा अन्य कोई शोषक पदार्थ मिले होते हैं। जहां पशुओं को बांधा जाता है, उस जगह की गोबर का प्रयोग खाद बनाने के लिए करते हैं।

तीन साल में दिखेगा असर

धीरज ने बताया कि यदि कोई किसान रसायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती अपनाता है, तो इसका असर उसे 2 से तीन साल बाद दिखाई देगा। हालांकि, स्वाद में अंतर पहले साल से दिखने लगेगा। 2 से 3 साल में उत्पादन भी ठीक-ठाक होने लगेगा। कई खेतों में 4 साल भी लग जाता है। इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी अच्छी हो जाएगी। ढाई बीघा में पारंपरिक खेती से मुनाफा करीब 12 से 15 हजार का होता है, जबकि जैविक खेती में ये पहले साल से ही 20 हजार तक का होता है। 10 साल लगातार जैविक खेती करने से खेत इसके अनुकूल हो जाता है, तब रासायनिक के मुकाबले दोगुना मुनाफा लिया जा सकता है।

नीम के पत्ते से बनाया स्प्रे

धीरज ने एक स्प्रे भी बनाया है। फसल में इल्ली या कीट लग जाने पर इसका छिड़काव करते हैं। इस स्प्रे की मांग आसपास के किसानों में काफी है। नीम के पत्ते और गोबर की राख आदि से बने इस स्प्रे के उपयोग से धीरज के गांव के अन्य किसान भी अपनी फसलों को कीट-पतंगों से बचा रहे हैं।

वर्मी कंपोस्ट बनाने की दे रहे ट्रेनिंग

अपनी फसलों के लिए धीरज खुद ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। साथ ही, गांव के अन्य किसानों को भी वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। धीरज ने बताया कि पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केंचुए डालते हैं। इसके बाद गोबर को जूट के बोरे से ढंक देते हैं। नमी के लिए बोर पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। गोबर को खाते हुए केंचुए डाले गए धीरे-धीरे आगे बढ़े होते जाते हैं। अपने पीछे वर्मी कम्पोस्ट बना कर छोड़ते जाते हैं।

ऐसे तैयार करते हैं जैविक खाद

जैविक खाद बनाने से पहले यह समझ लेना होगा कि किस अनुपात में क्या मिलाना है। अगर 10 किलो गोबर से खाद बनानी है, तो उसके लिए अन्य मिश्रण इस प्रकार रहेगा। 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो चोकर, 1 किलो मिट्टी का मिश्रण तैयार करना चाहिए। इन पांच तत्वों को मिलाते हैं। मिश्रण बन जाने के बाद इसमें 1 से 2 लीटर पानी डाल दें। अब इसे 20 दिनों तक किसी ड्रम में रख दीजिए। ध्यान रखें कि इस ड्रम पर धूप न पड़े। अच्छी खाद बनाने के लिए इस घोल को प्रतिदिन 1 बार अवश्य मिलाएं। 20 दिन बाद ये खाद बन कर तैयार हो जाएगी। यह खाद सूक्ष्म जीवाणु से भरपूर रहेगी। खेत की मिट्टी की सेहत के लिए अच्छी रहेगी।

कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी छोड़ शुरू की खेती

शिमला मिर्च से 20 लाख कमाई का लक्ष्य

इधर, शिवपुरी जिले में शिमला मिर्च के जरिए किसान हर्षवर्धन मजेजी ने 20 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य इस सीजन में रखा है। अभी तक वह अपने खेत से लगभग 100 क्विंटल शिमला मिर्च निकाल चुके हैं। आने वाले समय में मौसम अनुकूल रहा तो शिमला मिर्च का अच्छा उत्पादन होगा, जिससे उन्होंने 20 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में यह शिमला मिर्च बाजार में 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। शिवपुरी जिले में परंपरागत खेती के तौर पर वैसे गेहूं, चना, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें ज्यादातर किसान करते हैं। लेकिन अब किसान अलग हटकर अपनी आमदनी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसलिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। परंपरागत खेती से हटकर शिवपुरी के किसान हर्षवर्धन मजेजी ने भी पांच बीघा में शिमला मिर्च उगाई है और शिमला मिर्च में ड्रिप-एरिगेशन पद्धति से 20 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है।

टमाटर का उत्पादन भी बढ़ाया

किसान हर्षवर्धन मजेजी ने बताया, वह पिछले दो साल से टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बीते साल उन्हें टमाटर से अच्छा लाभ हुआ। इस साल भी उन्होंने अपने लगभग 100 बीघा के खेत में टमाटर किया है। किसान मजेजी ने बताया कि शिवपुरी का टमाटर दिल्ली, आगरा, कानपुर, ग्वालियर और झांसी आदि स्थानों पर जा रहा है।

खाने के साथ लिपस्टिक बनाने में होगा इस्तेमाल

वैज्ञानिकों ने विकसित की मिर्च की नई किस्म

अब प्राकृतिक कलर बाजार में क्रांति सी आ जाएगी

भोपाल/वाराणसी। जागत गांव हमार

वैज्ञानिकों ने मिर्च की एक ऐसी किस्म विकसित की है, जो खाने के काम तो आएगी ही साथ ही इससे मिलने वाले सुर्ख रंग का इस्तेमाल सौंदर्य प्रशाधन बनाने में भी किया जाएगा। मिर्चों की अनोखी इस हाइब्रिड प्रजाति का नाम वीपीबीसी-535 है, इसका नाम काशी सिंदूरी भी है। इसे वाराणसी स्थित आईसीएआर-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। विदेशों में मिर्च से रंग बनाने की कई प्रजातियों पर काम हो रहा है, लेकिन भारत में काशी सिंदूरी मिर्च की एकमात्र प्रजाति है, जिसे उत्तर प्रदेश के जलवायु को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसकी खेती को लेकर किसानों में भी उत्साह है। आईवीवीआर के निदेशक तुषार कांति बेहरा का कहना है कि आईआईवीआर लंबे समय से मिर्च पर काम कर रहा है और इस अवधि में कई सारी किस्में भी किसानों को उपलब्ध कराई गई है। मिर्च काशी सिंदूरी यानि पैप्रिका प्रजाति की खेती पहली बार हो रही है। जब यह मिर्च पक जाती है तो, इसका पूरा रंग लाल हो जाता है। इसमें एक औषधिय गुण होता है, जिसे ओलियोरेजिन कहते हैं। औषधिय गुण के कारण दवाई में और लाल रंग के रूप में सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंदूरी काशी मिर्च रंग के पिग्मेंट को सब्जी, सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक और मेडिसिन में इस्तेमाल करने से प्राकृतिक कलर मार्केट में क्रांति सी आ जाएगी। सिंथेटिक रंग के हानिकारक प्रभावों से करोड़ों नागरिकों को आसानी से बचाया जा सकता है। मिर्च की इस किस्म को यूपी ट्रॉपिकल के हिसाब से तैयार किया गया है। भारतीय सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल बाजार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्य के साथ दुनिया का आठवां सबसे बड़ा बाजार है और यह 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इस वृद्धि को बढ़ावा देने वाले त्वचा देखभाल और सौंदर्य प्रसाधनों के साथ बाजार 2030 तक दोगुना होने की उम्मीद है। भारतीय उपभोक्ताओं के बीच हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों की बढ़ती मांग भी निर्माताओं के लिए व्यापक विकास अवसर पैदा कर रही है।

सरकारी समर्थन की दरकार

सरकार को सब्जियों का समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। लेकिन, काशी सिंदूरी मिर्च की खेती एक संभावना है। यदि काशी सिंदूरी मिर्च की खेती होती है तो पूर्वांचल में मिर्च की खेती करने वाले लाखों किसानें मालामाल हो सकते हैं। इनके दिन फिर जाएंगे और सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों पर भी मुहर लगेगी। वहीं वाराणसी के जिला उद्यान निरीक्षक ज्योति कुमार सिंह ने बताया कि अगर सरकार से आधिकारिक समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है, तो काशी सिंदूरी की खेती को बहुत बढ़ावा मिल सकता है।

विदेश भी जा रही मिर्च

वाराणसी से चालीस किमी दूर मिर्जापुर जनपद में मेड़िया गांव चालीस फीसदी किसान मिर्च की खेती कई दशकों से करते आ रहे हैं। यही नहीं, यूपी के बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर जैसे जिलों में किसान मिर्च की खेती से जुड़े हुए हैं। इन जिलों से मिर्च दुबई, ओमान, कतर, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में निर्यात की जाती है।

किसानों की बढ़ जाएगी आय

किसान को लगा कि काशी सिंदूरी मिर्च की खेती किसानों के लिए बहुत पैसा कमाने का रास्ता हो सकती है। सामान्य मिर्च 30 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकती है, लेकिन अधिक होने पर 10 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर सकती है। दूसरी ओर काशी सिंदूरी 90 रुपए प्रति किलो तक बिक सकती है, उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा होने के लिए किसानों के पास एक अनुबंध होना चाहिए जो उन्हें आश्वस्त करे कि उनकी पूरी उपज बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी जाती है।

सिंदूरी मिर्च की खेती प्रायोगिक तौर पर शुरू

पप्पू सिंह ने आईआईवीआर से मिले बीजों से काशी सिंदूरी मिर्च की खेती प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दी है। बेहरा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों के अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनिंदा किसानों को काशी सिंदूरी की किस्म वितरित की गई है। नियमित मिर्च के 50 किलो के बैग की कीमत को तोड़ते हुए, पप्पू सिंह ने कहा कि बीज, सिंचाई, कीटनाशक, खाद, तुड़ाई और ढुलाई का खर्च जोड़ दें तो हमें मुनाफा नहीं मिल रहा है। इन दिनों सामान्य मिर्च की खेती में एक पचास किलोग्राम बैग पर लागत इस प्रकार है- तुड़ाई का दो सौ रुपए, ढुलाई का चालीस रुपए, सिंचाई, दवा और अपनी मेहनत को जोड़ दें तो हमें आशातीत मुनाफा नहीं हो रहा है।

किसानों को नहीं मिल रहा सही दाम

वाराणसी जिले के लोहटा गांव के एक युवा किसान बबलू ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने शिकायत की कि तीखी मिर्च की खेती से शुरुआत में मिलने वाले उत्पादन से ठीक आय हो जाती है। जैसे ही मंडियों में मिर्च की आवक बढ़ती है। व्यापारी औने-पौने दामों में माल खरीदने लगते हैं। लेकिन, काशी सिंदूरी की खेती हमारे जैसे हजारों किसानों के जीवन में बदलाव का सबब बन सकती है। इसके लिए सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियों को किसानों के संपर्क में लाया जाय। जनपद में मिर्च से रंग बनाने की इकाई लगाई जाए। इसके बाद फिर आय बढ़ाने के लिए पैप्रिका मिर्च की खेती के लिए किसानों को जागरूक और प्रत्साहित किया जाए।

काशी सिंदूरी की खेती की विधि

आईसीएआर-आईआईवीआर, वाराणसी द्वारा विकसित इस मिर्च को वीपीबीसी-535 कहा जाता है। इसमें उच्च मात्रा में ओलेरोसिन (15 प्रतिशत) होता है। यह प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल तक उपज दे सकता है। सामान्य मिर्चों का उत्पादन थोड़ा अधिक हो सकता है, क्योंकि उनमें अधिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। काशी सिंदूरी के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 400-500 ग्राम बीज की जरूरत होती है। काशी सिंदूरी की खेती रबी और खरीफ दोनों मौसमों में की जा सकती है। जो किसान वैज्ञानिक रूप से इस किस्म की खेती करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें जुलाई/अगस्त के महीनों में नर्सरी तैयार करनी चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि बीज बोने के 30 दिनों के बाद, पौधे को 45 सेमी की दूरी पर प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए, प्रत्येक पंक्ति 60 सेमी की दूरी पर होनी चाहिए। जब खेत तैयार किया जा रहा हो तो लगभग 20-30 टन प्रति हेक्टेयर कम्पोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। मिर्च को प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होती है।

-धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपए क्विंटल

धान उपार्जन में किसान स्वयं चुन सकेंगे केंद्र

भोपाल। जागत गांव हमार

समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल)	
धान	2040 रुपए
ज्वार	2970 रुपए
बाजरा	2350 रुपए
उपार्जन अवधि	
धान	28 नवंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक
बाजरा	1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक

राज्य शासन द्वारा खरीफ 2022-23 उपार्जन में नया प्रावधान कर अब किसान को अपनी अनाज के उपार्जन के लिए स्वयं अपनी पसंद एवं सुविधा के अनुसार उपार्जन केन्द्र का चुनाव करने की सुविधा दी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि किसान को उसकी उपज का मूल्य का भुगतान पीएफएमएस से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। सिंह मंत्रालय में खरीफ उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम तरूण पिथौड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। खाद्य मंत्री ने बताया कि खरीफ उपार्जन 2022-23 की नीतियों में किसानों के हित एवं सुविधा को देखते हुए नए प्रावधान किए गए हैं। अब वृद्ध एवं असक्षम कृषक की खरीदी नॉमिनी के माध्यम से भी की जा सकेगी। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर बायोमेट्रिक डिवाईस अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। उपार्जन प्रभारी एवं कृषक के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी देयक जारी किए जाएंगे। सत्यापन की व्यवस्था ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाईस से की जाएगी। गोदाम स्तरीय केन्द्र पर संस्थाओं द्वारा उपार्जन की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों से कहा कि राशन का वितरण किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होना चाहिए।

त्रि-स्तरीय निरीक्षण व्यवस्था

प्रमुख सचिव खाद्य उमाकांत उमराव ने बताया कि उपार्जन केन्द्र एवं भंडारण वाले गोदामों का तीन बार, उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व, उपार्जन के दौरान एवं उपार्जन समाप्त होने पर निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में कम वर्षा होने से गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान का पंजीयन एवं पैदावार कुछ कम रही है।

5 राज्यों ने कृषि वैज्ञानिकों ने लिया प्रशिक्षण और देखा माडल

छोटे एवं मझौले किसानों के लिये वरदान है जवाहर मॉडल खेती

जबलपुर। कृषि महाविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत संचालित मृदा विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं आचार्य डॉ. एन. जी. मित्रा के मार्गदर्शन में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पोषित "सेंटर आफ एडवांस फैकेल्टी" (काफ्ट) ट्रेनिंग में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आए कृषि वैज्ञानिकों को "प्राकृतिक खेती- चुनौतियां एवं अवसर" पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान 5 राज्यों के विभिन्न संस्थानों से आये कृषि वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जवाहर मॉडल का भ्रमण कराया गया। जवाहर मॉडल के प्रमुख डॉ. मोनी थॉमस, प्रमुख वैज्ञानिक ने बताया कि यह छोटे एवं मझौले किसानों के लिये एक वरदान है। हमारे मझौले एवं छोटे किसान कम लागत में वर्ष भर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करके लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि कम लागत एवं कम जगह पर भी किसान जवाहर मॉडर के माध्यम से खेती करके एक से डेढ़ माह में ही मुनाफा कमाना शुरू कर सकते हैं। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है या फिर पथरीली, ककरीली वाली जमीन या फिर छतों पर बोरी में मिट्टी भरकर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती कर जैविक रूप से खाद्यान्न उत्पाद की प्राप्ति कर सकते हैं। जवाहर मॉडल में प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. मोनी थॉमस और उनकी टीम के डॉ. नीरज त्रिपाठी, जितेन्द्र पटेल, कमलेश पटेल, राजेश यादव, निर्मलपंथी, ध्रुव पटेल द्वारा कार्य किया जा रहा है। व्याख्यान, चिंतन एवं दिशा दृष्टि पर वैचारिकी एवं शोध पर चर्चा की।

उद्योगों की मांग के अनुरूप 10 नवीन व्यवसाय पाठ्यक्रम प्रारंभ

राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः जैविक खेती पाठ्यक्रम में सबसे अधिक रुझान

भोपाल। जागत गांव हमार

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के द्वारा प्रारंभ किए गए कृषि, बागवानी जैसे पाठ्यक्रम की पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ा है। इस वर्ष 86 हजार 263 विद्यार्थियों ने स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में जैविक खेती विषय चुना है।

पिछले वर्ष 76 हजार 518 विद्यार्थियों ने इस विषय का चयन किया था। इसी तरह इस वर्ष 9 हजार 38 विद्यार्थियों ने बागवानी विषय का चयन किया है। महाविद्यालय में इस वर्ष कृषि से जुड़े वर्मी कंपोस्टिंग, डेयरी प्रबंधन और औषधीय पौधे, खाद्य सुरक्षा एवं प्रसंस्करण जैसे व्यवसायिक विषयों को 12,516 विद्यार्थियों ने चुना है। उच्च शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि सभी विज्ञान महाविद्यालयों में नर्सरी प्रारंभ की जाए। महाविद्यालयों के अतिरिक्त विक्रम विवि, उज्जैन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भी कृषि पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने शासकीय, निजी विवि तथा महाविद्यालयों द्वारा गांव गोद लेने, कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति के माध्यम से कार्रवाई करने और 30 भूमि विहीन शासकीय महाविद्यालयों को शीघ्र भूमि आवंटन कराने के भी निर्देश दिए।

10 नए व्यवसाय विषय प्रारंभ

बैठक में बताया गया कि उद्योगों की मांग के अनुरूप इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत फैशन डिजाइनिंग, एग्री मार्केटिंग, कैटरिंग, मैनेजमेंट बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट, कैटरिंग मैनेजमेंट, प्लांट डिसीसेस एंड प्रोटेक्शन, मृदा विज्ञान और उर्वरक, सूचना प्रौद्योगिकी, इवेंट मैनेजमेंट, पोल्ट्री मैनेजमेंट पर 10 नवीन व्यवसाय विषय प्रारंभ किए गए

52 जिलों के प्रस्ताव पर चर्चा

बैठक में संभागीय मुख्यालयों पर उत्कृष्टता शिक्षा संस्थान एवं 52 जिलों में आदर्श महाविद्यालय चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट महाविद्यालय में आवश्यकता अनुसार बस परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव शैलेन्द्र सिंह, आयुक्त कर्मवीर शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अरब देशों में बढ़ी बैतूल के बीन्स की डिमांड

सतीष साहू, बैतूल। जागत गांव हमार

बीन्स ने एक किसान की किस्मत बदल दी। दोस्त की सलाह पर परंपरागत खेती के साथ बीन्स उगाना शुरू किया। उनके खेत की बीन्स की सप्लाई बैतूल, नागपुर और मुंबई की जाती है। मुंबई के रास्ते अरब देशों तक बीन्स सप्लाई की जा रही है। अब हर साल 12 लाख रुपए कमा रहे हैं बैतूल के नवनीत वर्मा। परिवार लंबे समय से परंपरागत खेती करता रहा है। पहले मक्का, गेहूं, सोयाबीन, गन्ना, मूंग और अरहर की खेती करते थे, लेकिन इन फसलों की लागत और मुनाफे का अंतर कम होता गया। ऐसे में जरूरी हो गया था कि खेती के तरीकों में बदलाव करें या खेती करना छोड़ दूसरा ऑप्शन अपनाएं। नवनीत ने परंपरागत के साथ वैकल्पिक खेती शुरू की। 10 एकड़ खेत के छोटे से हिस्से में सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। इस दौरान खेत में स्ट्राबैरी, बेर, मौसंबी और मुनगा की खेती करने लगे। इसमें भी उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं दिखा। उनके किसी मित्र ने बीन्स की खेती करने की सलाह दी। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के लिए एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट नवनीत वर्मा ने बीन्स की खेती शुरू कर दी। लगातार तीसरे साल मुनाफा कमाने लगे। पुराने कर्ज को भी चुका दिए। नवनीत कहते हैं कि बीन्स 52 दिन में उपज देने लगती है।

शेड नेट में लगा रहे पोल वीन्स

नवनीत ने एक एकड़ क्षेत्र में शेड नेट तैयार कराया। 22 लाख की लागत के इस शेड में पहले टमाटर, गोभी, ककड़ी लगाते थे, लेकिन अब बीन्स की खेती कर रहे हैं। अब तक यही समझा जाता था कि यह फसल परागण के बिना नहीं होती। यानी खुले वातावरण में ही होती है। हमने इसे शेड में लगाया। इसकी फसलों में 80 प्रतिशत जैविक खाद और 20 प्रतिशत रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं।

गमले में भी उगा सकते हैं बीन्स

बाकला या कॉमन बीन (वैज्ञानिक नाम :फैसेयोलस वल्गैरिस) जो मीजो अमरीका और एंडीज पर्वत पर मूलत: उगता था। अब सभी देशों में इसकी खेती होती है। इसकी फलियां और बीज ही इसके उत्पाद होते हैं। इसकी पत्तियां कहीं-कहीं हरी सब्जी के काम आती हैं। इसका भूसा मवेशियों के लिए काम में आता है। बीन्स एक प्रकार की सब्जी है, जो बेल या झाड़ीदार पौधे के रूप में उगती है। बीन्स वसंत के मौसम में सबसे अच्छी तरह विकसित होती है। ठंडे मौसम में गमलों में भी बीन्स उगा सकते हैं, क्योंकि गमले की मिट्टी का तापमान खेत की मिट्टी के मुकाबले गर्म होता है। यह बीन्स के उत्पादन के लिए उपयुक्त रहता है। पौधे को ठंड से बचाने के लिए गमले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित कर सकते हैं।

चार किलो बीज में 20 टन की उपज

नवनीत ने बताया कि शेड नेट में सेल्फ पॉलिनेटेड (स्व-परागण) फसलें ही लगाई जाती रही हैं। बीन्स का बीज महज 2200 रुपए किलो में मिल जाता है। शेड में सिर्फ 4 किलो बुवाई होती है। 52 दिन में उपज आना शुरू हो जाती है। छह से सात महीने के अपने जीवनकाल में चार किलो बीज के पौधों से 18 से 20 टन की उपज मिल जाती है। शेड की वजह से कीटनाशक का खर्च भी बच जाता है। बीन्स की बोवनी तब करें, जब मिट्टी कम से कम 48 डिग्री एफ तक गर्म हो गई हो। मिट्टी में अधिक नमी अंकुरण में देरी करेगी और बीज सड़ने का खतरा रहेगा।

स्थानीय स्तर पर बीन्स की अच्छी कीमत मिल जाती है। लोकल बाजार में यह 60 रुपए किलो तक बिक जाती है। इसे बाजार में बेचे जाने पर इसकी कीमत और बढ़कर मिलती है। आमतौर पर यह बीन्स बिना रेशा वाली होती है, इस वजह से इसे बेहद पसंद किया जाता है। बैतूल से बीन्स की उपज नागपुर तक भेजते हैं। नागपुर से मुंबई-पुणे और फिर अरब देश अल्जीरिया, मिस्त्र, बहरीन, जार्डन, कुवैत, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, कतर आदि तक इसे डिब्बे में पैक करके भेजा जाता है। फसल की खास विशेषता यही है कि इसका कीपिंग टाइमिंग अधिक है। यानी इसे काफी समय तक रखा जा सकता है। बगैर फ्रीज में रखे भी ताजी रह सकती है। न तो इसकी गुणवत्ता में कमी आती है और न ही रंग, वजन और स्वाद में परिवर्तन आता है।

मप्र में 30 लाख 69 हजार लंपी टीकाकरण पूर्ण

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया है कि प्रदेश में लंपी का प्रकोप लगभग समाप्तप्राय है। पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा पड़ोसी राज्यों में लंपी उदभेद के साथ ही अपनाई गई सतर्कता से देश में सबसे बड़े पशुधन वाले राज्य मध्यप्रदेश में पशुओं में लंपी रोग का संक्रमण नियंत्रित रहा। प्रदेश में अब तक 30 लाख 69 हजार टीकाकरण हो चुका है।

27 हजार से अधिक पशु स्वस्थ

लंपी से कुल 35 जिलों के 4 हजार 817 गांव के पशु प्रभावित हुए हैं। प्रभावित पशुओं की संख्या 29 हजार 257 है। इसमें से 27 हजार 481 पशु स्वस्थ हो चुके हैं।

जिलावार टीकाकरण

रतलाम जिलें में 1 लाख 12 हजार 480 पशुओं को लंपी का टीका लगाया गया। इसी तरह उज्जैन-112314, नीमच-116373, मंदसौर-113726, आगर-मालवा-57190, शाजापुर-80083, देवास-108310, खण्डवा-160987, इंदौर-104647, झाबुआ-161700, धार-208578, बुरहानपुर-113572, अलीराजपुर-174000, खरगौन-239883, बड़वानी-133409, बैतूल-271649, हरदा-48254, राजगढ़-104779, नर्मदापुरम-46975, सीहोर-56790, भोपाल-21920, भिंड-50200, मुरैना-52850, श्योपुर-24083, ग्वालियर-67174, शिवपुरी-67696, दतिया-13722, गुना-79200, अशोकनगर-16108, नरसिंहपुर-29171, बालाघाट-51809, जबलपुर-29274, छिंदवाड़ा-33800, कटनी-2008 और टीकमगढ़ जिले में 4250 पशुओं को टीका लगाया गया।

केंद्रीय कृषि मंत्री से राज्य मंत्री कुशवाह ने की भेंट

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल से राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने की मांग

प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण संस्थान की हो स्थापना

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय खाद्य प्र-संस्करण और जलशक्ति नियोजन मंत्री प्रह्लाद पटेल से प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने नई दिल्ली में भेंट की। कुशवाह ने केंद्रीय मंत्री से मध्यप्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण संस्थान की स्थापना के लिए पत्र सौप कर स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश की जलवायु उद्यानिकी फसलों के अनुकूल है और पिछले वर्षों में प्रदेश में फल, सब्जी और मसाला उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना से प्रदेश के किसानों को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश में उच्च तकनीक वाले खाद्य प्र-संस्करण संस्थान की स्थापना से प्रदेश के किसानों

के साथ ही सीमावर्ती राज्यों के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने नई दिल्ली में भेंट की। राज्य मंत्री कुशवाह ने केंद्रीय मंत्री तोमर से ग्वालियर में एक्सीलेंस ऑफ फ्लोरीकल्चर बहुउद्देशीय गार्डन की स्थापना के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। कुशवाह ने कहा प्रस्तावित फ्लोरीकल्चर गार्डन में पुष्प उद्यान, लोटस पोंड, आर्किड उद्यान, नेचरोपेथी ध्यान केंद्र, रिसोर्ट और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इस पर 70 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में गार्डन की स्थापना के लिए 10 करोड़ प्राप्त हुए है।

किसानों का टूट रहा सोलर पंप का सपना

सिर्फ 12 फीसदी लक्ष्य तक ही पहुंच सका ऊर्जा विकास निगम, तीन साल में 10 हजार को भी नहीं मिला लाभ

प्रदेश में दम तोड़ रही 'कुसुम'

अरविंद मिश्र। भोपाल

अक्षय उर्जा को बढ़ावा देने सरकार जहां एक ओर दावे कर रही है। वहीं योजनाओं के क्रियांवयन की स्थिति जिम्मेदारों को कठघरे में खड़ा कर देती है। कुसुम योजना के घटक-दो में शामिल व इससे अछूती नहीं है। क्योंकि पर्याप्त बजट के अभाव में 2019 से शुरू हुई इस योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा राज्य में 10 हजार की संख्या भी नहीं छू पाया है। जबकि अक्षय उर्जा को बढ़ावा देने केंद्र सरकार द्वारा 57 हजार प्रकरणों की स्वीकृतियां दी गई हैं। खास बात यह है कि देश भर में योजना के तहत 20 लाख कृषि विद्युत पंपों की स्थापना का लक्ष्य लिया गया था। बावजूद इसके तीन साल बाद यानी 30 सितंबर 22 की स्थिति में सिर्फ 7 हजार ही लग पाए हैं। जबकि इसके पहले और अंतिम घटक की प्रगति सूची में अब तक शून्य दर्ज है। इसके पीछे राज्य सरकार का योजना प्रावधान के मुताबिक 30 प्रतिशत राशि नहीं दे पाना है। इसके कारण अपने अंश की करीब 70-70 हजार रुपए की राशि सरकार के खाते में जमा कराने के बाद भी 1100 किसान खेतों में सोलर पंप की स्थापना का अब तक इंतजार कर रहे हैं। जबकि प्रतिवॉट 5 हजार की राशि जमा कराने के बाद 15 हजार पंजीकृत किसानों का नंबर कब आएगा इसका जबाव विभाग के पास भी नहीं है।

असरहीन सीएम हेल्पलाइन में शिकायत

योजना के तहत राशि जमा कराने वाले किसानों का कहना है कि कार्य में तेजी लाने के लिये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन प्रत्येक बार यह असरहीन साबित हुई। इनका कहना है कि पहले करोना का बहाना था अब संतोषजनक उत्तर ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसमें साफ कहा जा रहा है कि विभाग को बजट का इंतजार है।

88 फीसदी का लक्ष्य बना चुनौती

योजना की मौजूदा स्थिति नवीनकरणीय उर्जा विभाग के लिये चिंता का विषय बन गई है। क्योंकि तय लक्ष्य का अब तक मात्र 12 प्रतिशत ही पूरा कर पाये हैं। हालांकि 9 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने वाले महाराष्ट्र को छोड़ दें तो किसी दूसरे राज्य की प्रगति 19 प्रतिशत से कम नहीं है। इसमें झारखंड ने तो सबको पछाड़ते हुए 50 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर चुका है। इसके बाद राजस्थान 31.9 और हरियाणा के साथ पंजाब 19 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं।

इसलिए भी है जरूरी

पैरिस समिट में तय प्रतिमान के अनुसार हम वर्ष 2030 तक देश की ऊर्जा आवश्यकता का 40 प्रतिशत, गैर फॉसिल बेस्ड ईंधन से पूरा करने का लक्ष्य हैं। बावजूद इसके हम क्लीन एनर्जी के लगभग 1 लाख 75 हजार मेगावॉट उत्पादन के लक्ष्य के क्रम में ही देश 69 हजार मेगावॉट ऊर्जा उत्पादित कर रहा है। जिसमें कुल उत्पादन का हमारे राज्य से योगदान 7 प्रतिशत से अधिक नहीं है। ऐसे में अक्षय उर्जा के क्षेत्र में त्वरित क्रियांवयन की जरूरत बनी हुई है। उन्होंने यह जरूर बताया कि कुसुम के इस दूसरे घटक का प्रदर्शन भले ही बेहतर नहीं है, लेकिन पहले और तीसरे घटक के कार्य दिखाई पड़ने लगे हैं। इससे संबंधित परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हम सौर उर्जा के क्षेत्र में निर्भरता की ओर बढ़ेंगे।

मंत्री नहीं मानते राशि का अभाव

पैसा जमा कराने के बाद सरकार जहां हितग्राहियों को लाभ नहीं दे पा रही है। वहीं नवीनकरणीय उर्जा विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग नहीं मानते

हैं कि बजट की कमी के कारण मप्र योजना क्रियांवयन में पीछे हैं। विषय से संबंधित 'जागत गांव हमार' से चर्चा के दौरान भी उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं था कि केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से इतर हितग्राही अंश की राशि जमा कराने के बाद भी सरकार 1100 किसानों के खेतों में अब तक सोलर पंप क्यों नहीं लगवा पाई है।

विदिशा कृषि मंडी में अचानक पहुंचे अशोक वर्णवाल

एसीएस ने किया मंडी का औचक निरीक्षण

विदिशा। जागत गांव हमार

कृषि विभाग के एसीएस अशोक वर्णवाल ने नवीन कृषि उपज मंडी विदिशा का भ्रमण कर यहां संचालित व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया । भ्रमण के दौरान उन्होंने कृषकों से संवाद कर मंडी में मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि कृषक बंधुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े इस तरह के प्रबंध कृषि उपज मंडी में सुनिश्चित किए जाएं।

भ्रमण के दौरान जिले के अधिकारी रहे साथ नवीन कृषि उपज मंडी के भ्रमण के दौरान श्री वर्णवाल ने मंडी परिसर में टूटी-फूटी सड़कों पर असंतोष जाहिर करते हुए मरम्मत कराने के निर्देश मौके पर दिए । भ्रमण के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव समेत कृषि विभाग के अधिकारीगण, नवीन कृषि उपज मंडी के अधिकारियों के अलावा अन्य मौजूद रहे। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया श्री वर्णवाल ने मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान प्रयोगशाला के कर्मियों से संवाद कर कृषकों के द्वारा मिट्टी परीक्षण करने की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर ही मिट्टी परीक्षण का लाभ ले चुके कृषक से मोबाइल पर बात की और मिट्टी परीक्षण के उपरांत किन-किन खाद का उपयोग कर रहे है और उसकी मात्रा की जानकारी ली।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)